(ग्रुप "डी" में सफाई वालों को छोड़कर)

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के मामले में, ग्रुप "बी", सी" और "डी" में 15 प्रतिशत का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मामले में, उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण, प्रतिनिधित्व का प्रतिशत पूरा नहीं हो पाया है। एक विशेष अभियान चलाया गया था और पिछली कुछ कमी पूरी की गयी थी सेवाओं में, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के सभी प्रयास किये जाते हैं।

इस्पात की मांग

901. श्री राम नरेश यादव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग और आगामी दो वर्षों में इस्पात की मांग और पूर्ति में होने वाले लगातार अन्तर को कम करने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : देश में इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये विभिन्न उपायों द्वारा समय-समय पर इस्पात के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं—

—वर्धित उत्पादन प्राप्त करने के लिये इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और संयंत्र और उपस्करों का उन्नत अनुरक्षण।

—इस्पात संयंत्रों को आदानों विशेष रूप से कोयले और बिजली की सप्लाई का प्रबोधन, ताकि बिना व्यवधान के उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

—विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को अपनी क्षमता वार्षिक 2.5 लाख टन तक बढ़ाने की अनुमति।

—निजी क्षेत्र में भारी क्षमता वाले नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना की अनुमति देना।

—विशेष रूप से विशिष्ट श्रेणियों की शेष मांग को आयात से पूरा किया जायेगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महानिदेशक का पद

902. श्री राम नरेश यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महानिदेशक का पद कब से रिक्त है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ख) उस पद पर विधिवत नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) महोदय, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग में भारत सरकार के सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं। कृषि और सहकारिता विभाग में भारत सरकार के सचिव दिनांक 5-4-90 से ही कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार संभाले हुये हैं। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली है। इस संबंध में आयोग की सिफारिश की प्रतीक्षा की जा रही है।

**Allotment of plots in Rohini**

903. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether in 1981 DDA had invited applications for allotment of residential plots under its Rohini Scheme;